



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 1982/चैत्र 30, 1904  
No. 145] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 1982/CHAITRA 30, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1982

का०अ० 272(अ) — 18 खण्ड/आई०डी०आर०ए०/82—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 277(घ)/18 खण्ड/आई०डी०आर०ए०/78, तारीख 20 अप्रैल, 1978 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18खख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रभूत सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंजाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों से उद्भूत या प्रोद्भूत सभी बाध्यताओं और दायित्वों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं, जिनके मसस स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर की, (1) मसस स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर, (2) मसस स्वदेशी काटन मिल्स, पारिजनेरी, (3) मसस स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी (4) मसस स्वदेशी काटन मिल्स, माऊताथ भंजन, (5) मसस उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर, और (6) मसस रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स, रायबरेली नामक उपक्रम, पक्षकार हैं या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रमों को लागू हो सकती हैं, प्रवर्तन ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उद्घोषित प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि तक निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि 20 अप्रैल, 1982 तक, जिसके प्रस्तावित यह तारीख भी सम्मिलित थी, बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 12 अप्रैल, 1983 तक और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18खख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 12 अप्रैल, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ाती है ।

[का० सं० 3(6)/78-सी०यू०एस]  
सी० के० मोदी, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 20th April, 1982

S.O. 273(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 277(E)/18FB/IDRA/78, dated the 20th April, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments, in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities

to banks and financial institutions), to which the industrial undertakings known as : (i) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Kanpur, (ii) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Pondicherry, (iii) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Naini, (iv) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Maunath Bhanjan, (v) M/s. Udaipur Cotton Mills, Udaipur and (vi) M/s. Rae Bareilly Textile Mills, Rae Bareilly, of M/s. Swadeshi Cotton Mills Company Limited, Kanpur, are parties or which may be applicable to such industrial undertakings, shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the obligation and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 20th April, 1982;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 12th April, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of 12th April, 1983.

[F. No. 3(6)/78-CUS.]

C. K. MODI, Jt. Secy.